मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में राजीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ बजट पूर्व संवाद किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटा राम देवासी उपस्थित थे।

राजीविका की प्रत्येक बहन पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बना रही है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बजट पूर्व संवाद किया

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दो हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि आजीविका संवर्धन हेतु प्रदान की गई।**

जयपुर, 16 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तीकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। राजस्थान में भी राजीविका के माध्यम से महिलाएं प्रदेश के विकास की मुख्यधारा में शामिल होकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि राजीविका की प्रत्येक बहन पारिवारिक आय बढ़ाने में योगदान दे रही है और पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बना रही है। शर्मा शुक्रवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में राजीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के निर्माण में भी आधी आबादी की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजीविका की लगभग 13 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। इनमें से मिलेनियर दीदी भी बन रही हैं। स्वयं सहायता समूहों ने सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं बेहतरीन प्रबंधक और उद्यमी हैं। साथ ही, महिलाओं ने ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने की मजबूरी से भी मुक्ति पाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 51 लाख ग्रामीण परिवारों को 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। साथ ही, 32 हजार ग्राम संगठन और 1 हजार से अधिक क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से राजीविका का मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि आजीविका संवर्धन के अंतर्गत, लगभग 36 लाख परिवार कृषि एवं पशुपालन आधारित गतिविधियों से जुड़कर काम कर रहे हैं।

शर्मा ने कहा कि राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि आजीविका संवर्धन हेतु प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि कृषि एवं पशुपालन और गैर-कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए साढ़े 3 हजार से अधिक उत्पादक समूहों का गठन किया गया है। इनके माध्यम से लगभग 3 लाख परिवारों को कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों में जोड़ा गया है। किसान परिवार की महिलाएं पशुपालन भी करती हैं। इसलिए हमारी सरकार पशुपालकों को दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दे रही है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटा राम देवासी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया, स्टेट मिशन निदेशक स्वयं सहायता समूह नेहा गिरि सहित, अन्य अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में राजीविका महिलाएं उपस्थित थे।

'एस आई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक केस के कई इनामी आरोपी विदेशों में छिपे हैं'

'ऐसे में इस मामले की जाँच संभवतः कई सालों तक चलेगी, फिर भी दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा'

-यादवेन्द्र शर्मा-

- **एस आई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की सुनवाई के दौरान मूल याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि इस परीक्षा में बड़े स्तर पर चीटिंग और पेपर लीक किया गया था और तत्कालीन राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण नियमों और नीतियों को नज़रअदांज़ करते हुए निजी व्यक्तियों को परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त किया था।**
- **इनमें से कुछ व्यक्तियों पर तो पहले भी पेपर लीक करने के आरोप थे।**
- **याचिकाकर्ताओं ने कहा, परीक्षा के पहले दिन बीकानेर से पेपर लीक गिरोह ने वॉटसऐप और इंटरनैट के जरिए अलग-अलग केन्द्रों पर पेपर बेच दिया था, इस पर एफआईआर भी हुई थी और फिर भी आरपीएससी ने पेपर रद्द कराने के संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया। परीक्षा आयोजित कराने की पूरी प्रणाली टूट चुकी थी और पेपर लीक गिरोह की सांठ-गांठ के साथ ही चल रही थी।**

जयपुर, 16 जनवरी। राजस्थान हाई कोर्ट में एस आई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किए जाने के खिलाफ व संबंधित मामलों में आज सुनवाई जारी रही। परीक्षा रद्द करने के पक्ष में मूल याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि इस मामले में एकल पीठ का आदेश दुरुस्त इसलिए है, क्योंकि वह एस आई टी की जांच रिपोर्ट की विस्तृत व तथ्यों को देखते हुए दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर वी सिंह , उनके सहायक अधिवक्ता जय वरदान सिंह और हरिंदर नील ने अदालत को बताया कि एसआईटी की रिपोर्ट कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक विस्तृत जांच है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि एस आई भर्ती परीक्षा के तीनों दिन बड़े ही विस्तृत तौर पर पेपर लीक हुआ, चीटिंग की गई।

उन्होंने बताया कि एस आई भर्ती परीक्षा के पहले दिन 13/09/2021 को बीकानेर के राम सहाय सेकेंडरी स्कूल से पूरव कालेर और तुलसा राम कालेर गैंग ने स्कूल के प्रिंसिपल और अधीक्षक के साथ मिलकर परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर चुराया और वॉट्सऐप व अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए अलग अलग केन्द्रों में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के हाथ पेपर बेचा। इस वारदात के खिलाफ न केवल बीकानेर में एफ आई आर दर्ज की गई थी, बल्कि कई सौ किलोमीटर दूर पाली में भी एफ आई आर दर्ज करी गई, क्योंकि वहां के अभ्यर्थियों के साथ भी यही पेपर कालेर गैंग द्वारा साझा किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि आर पी एस सी के अधिकारियों व अध्यक्ष ने इतनी बड़ी वारदात को नज़रअंदाज़ किया और पेपर रद्द किए जाने के पक्ष में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यह स्वयं ही स्पष्ट करता है कि परिक्षा निष्पक्ष रूप से कराने की प्रणाली ऊपर से लेकर नीचे तक टूट चुकी थी और पेपर लीक गिरोह से सांठगांठ के साथ चल रही थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि परीक्षा के दूसरे दिन 14/09/2021 को जयपुर के बाल भारती स्कूल से पेपर लीक कराया गया, जिसमें परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार सेंट्रल सुपरिटेंडेंट राजेश खंडेलवाल की अहम भूमिका बताई जाती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राजेश खंडेलवाल ने ही बाल भारती स्कूल में यूनिक भांभू को अधीक्षक और इनविजिलेटर के पद पर नियुक्त कराया, जिसने स्कूल के प्रिंसिपल के दफ्तर से पेपर के फोटो खींच कर लीक करे। उल्लेखनीय है कि भांभू एक सरकारी अफसर नहीं, बल्कि कई पेपर लीक मामलों में मुख्य आरोपी है। उन्होंने कहा कि भांभू विदेश में छिपा हुआ इनामी आरोपी है, जिसे आज तक पकड़ा नहीं गया है। उन्होंने यह भी बताया कि एस ओ जी की रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट है कि भांभू ने पेपर जगदीश बिश्नोई गैंग को बेचा था, जिसने पूरे प्रदेश में फैले हुए तंत्र की मदद से कई परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों को पेपर मुहैय्या कराया और एक चलती वैन में बैठे परीक्षा पेपर का समाधान लिखने वाले समाधानकर्ताओं की मदद से परीक्षा में उत्तर लिखने की गैर कानूनी सुविधा भी मुहैय्या कराई। उन्होंने कहा कि जगदीश बिश्नोई गैंग ने सुरेश ढाका गैंग को भी पेपर बेचा था, जिसने रंगोली गार्डन्स में छिपे हुए अपने गिरोह के साथियों की मदद से कई और अभ्यर्थियों को बेचा और समाधान भी दिया। एस ओ जी की जांच में यह भी लिखा है कि सुरेश ढाका, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है, भी फरार है और विदेश में छुपा हुआ है, जिसपर एक लाख रुपए का इनाम भी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब इस मामले के मुख्य आरोपी ही नहीं पकड़े गए है तो राज्य सरकार जांच पूर्ण कब और कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच कई वर्षों तक जारी रह सकती है, परंतु दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। इस मामले में सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी, हालांकि अदालत ने महाधिवक्ता को मौखिक रूप से दिए गए आदेश कि, अपीलें दायर किए जाने के बाद से पुलिस ने एस आई भर्ती प्रकरण में कितने और आरोपियों को गिरफ्तार किया और इंटेरोगेट किया, इसकी जानकारी साझा करने पर आज जोर नहीं दिया, परंतु हो सकता है सोमवार को राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी अदालत में साझा की जाए।

राष्ट्रमंडल देशों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विकास यात्रा, लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मूल्यों पर भी सकारात्मक संवाद किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से प्रदेश की वैश्विक पहचान सशक्त होती है तथा पर्यटन, संस्कृति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर प्राप्त होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा प्रतिनिधियों के स्वागत एवं प्रवास के लिए व्यापक और सुव्यवस्थित तैयारियाँ की गई हैं, ताकि अतिथियों को एक यादगार और सुखद अनुभव मिल सके। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि शनिवार सायंकाल कांस्टीट्यूशन क्लब में अतिथियों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुतियाँ होंगी। रात्रि भोज में राज्यपाल हरि भाऊ बागड़े, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष, मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव सहित, अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे।

दिग्गी राजा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। 2003 में राज्य में कांग्रेस की सत्ता से विदाई के बाद, दिग्विजय सिंह ने अगले 10 वर्षों तक चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में सक्रिय राजनीति में वापसी की और 2014 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए।

सहायक अभियोजन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विचारणीय नहीं है, बल्कि उत्तर पुस्तिका की जांच की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने सहायक अभियोजक अधिकारी के 180 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसकी मुख्य परीक्षा में तीन हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ चार अभ्यर्थियों को ही पास घोषित किया गया। आयोग के परीक्षा परिणाम के अनुसार, अधिकांश अभ्यर्थी तय न्यूनतम अंक भी हासिल नहीं कर पाए, जबकि इस परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिन्होंने पूर्व में सिविल जज की लिखित परीक्षा पास की थी। ऐसे में आयोग की ओर से जारी यह परिणाम मनमाना और अव्यावहारिक है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व में सफल अभ्यर्थियों और दस असफल अभ्यर्थियों की कॉपी पेश करने के आदेश दिए थे।

मारिया मचाडो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कितना अद्भुत भाव है। धन्यवाद मारिया!

दूसरी ओर नोबेल समिति और नोबेल संस्थान ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि एक बार नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने के बाद उसे हस्तांतरित, साझा या रद्द नहीं किया जा सकता है।

नोबेल समिति ने उन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दी जिनमें कहा गया था कि मारिया कोरिना मचाडो ने 15 जनवरी, को व्हाइट हाउस में अपनी मुलाकात के दौरान अपना पदक ट्रंप को उपहार के रूप में सौंप दिया। समिति ने कहा, "एक बार नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद, इसे रद्द नहीं किया जा सकता, न ही साझा किया जा सकता है और न ही दूसरों को हस्तांतरित किया जा सकता है। यह निर्णय अंतिम है और हमेशा के लिए मान्य रहता है।"

तृणमूल नेता मुकुल रॉय को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

- **सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रॉय को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।**

नयी दिल्ली, 16 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कोलकाता उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें वरिष्ठ राजनेता मुकुल रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा।

मुकुल रॉय ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर कृष्णनगर उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। उन पर आरोप लगाया गया था कि वह बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय ने उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए याचिकाएं दायर की थीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष ने हालांकि रॉय को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अधिकारी ने कोलकाता उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को रद्द कर दिया था और रॉय को अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया था।

याचिकाकर्ता की ओर से उच्चतम न्यायालय में पेश हुए अधिवक्ता प्रीतिका द्विवेदी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने एक मौजूदा विधायक को अयोग्य घोषित करने का निर्देश देकर न्यायिक समीक्षा की अपनी सीमित शक्ति का उल्लंघन किया है।

मुम्बई और पुणे में भाजपा बहुमत के करीब

जनता ने ठाकरे बंधुओं और पवार परिवार की एकता में रूचि नहीं दिखाई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **खबर लिखे जाने तक बीएमसी चुनावों में भाजपा का गठबंधन 115 सीटों पर आगे है और ठाकरे बंधु 77 सीटों पर आगे चल रही थी, उसी प्रकार पुणे में भी एनसीपी मात्र 6 वार्डों में आगे है और भाजपा 80 वार्डों में आगे चल रही है।**

नई दिल्ली, 16 जनवरी। महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनावों की मतगणना के बीच मुंबई की बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) में भाजपा गठबंधन ने आधे से अधिक सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके बाद ठाकरे चचेरे भाई आते हैं। अभी मतगणना जारी है।

पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़, जो शरद पवार और अजित पवार के गढ़ माने जाते हैं, के चुनावों में पवार परिवार के पुनर्मिलन की रणनीति बड़ी हद तक नाकाम होती दिख रही है, क्योंकि दोनों ही शहरों में भाजपा ने बड़ी बढ़त बना ली है। एनसीपी के दोनों गुटों के मिल जाने से इन दोनों नगर निगमों में पवार-परिवार के आसार बहुत अच्छे माने जा रहे थे।

बीएमसी में भाजपा नेतृत्व वाला गठबंधन 115 वार्डों में आगे है। भाजपा 86 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 29 वार्डों में आगे है।

ठाकरे चचेरे भाई 77 वार्डों में पीछे हैं और इस धनवान नगर निकाय पर नियंत्रण बनाए रखने के उनके प्रयास सुस्त दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 71 वार्डों में आगे है, जबकि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) छह वार्डों में बढ़त पर है।

ताज़ा रुझानों के अनुसार, पुणे में भाजपा 80 वार्डों में आगे है। पवारों के गठबंधन में एनसीपी (अजित पवार) केवल छह वार्डों में आगे है, जबकि एनसीपी (शरद पवार) तीन वार्डों में बढ़त पर है। कांग्रेस तीन वार्डों में आगे है और वह ठाकरे भाइयों (उद्धव की शिवसेना और राज की मनसे) के साथ गठबंधन में है, जो किसी भी वार्ड में आगे नहीं हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पुणे नगर निगम चुनाव अकेले लड़ रही है और अब तक किसी भी वार्ड में आगे नहीं है।

पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम, जिसे बीएमसी के बाद सबसे समृद्ध माना जाता है, वर्ष 2017 से शरद पवार की अविभाजित एनसीपी के पास रहा है। लेकिन आक्रामक प्रचार के बावजूद, पवार इस गढ़ को भी खोते नजर आ रहे हैं। एनसीपी (अजित पवार) 37 सीटों पर आगे है, जबकि एनसीपी (शरद पवार) केवल एक वार्ड में बढ़त बनाए हुए है। दूसरी ओर, भाजपा 77 वार्डों में आगे निकल चुकी है।

पिंपरी-चिंचवाड़ में दोनों ठाकरे मिलकर केवल एक वार्ड में आगे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 10 वार्डों में बढ़त पर है। ताज़ा रुझानों के अनुसार, कांग्रेस अब तक किसी भी वार्ड में बढ़त नहीं बना पाई है।

चाचा-भतीजे, जो पहले एनसीपी के हिस्से के रूप में साथ काम कर चुके थे, 2023 में अलग हो गए थे, जब अजित पवार ने महाराष्ट्र में भाजपा से गठबंधन कर लिया था। शरद पवार गुट की एनसीपी राज्य और केन्द्र दोनों में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रही है।

पिछले वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की भारी जीत के बाद, दोनों के बीच सुलह की मांगें उठने लगी थीं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600